MR. CHAIRMAN: The question is ;

"That this House do agree with the Eightieth Report of the Committee on Private Members, Bills and Resolutions presented to the House on the 14th August, 1984."

— —

The motion was adopted.

15.35 hrs.

RESOLUTION RE. DEVELOPMENT OF RURAL AREAS *Contd.*

MR. CHAIRMAN : The House will now continue further discussion of the following resolution moved by Shri Ram Lal Rahi on 27th April,1984:—

"This House is of the opinion that Government have failed to ameliorate the lot of low income group people through planned development of rural areas on account of serious inadequacies in the administrative machinery and therefore recommends to the Government to devise pragmatic policies by laying emphasis on education and moral values and by revamping the administrative structure so as to ensure integrated development of the rural areas for upliftment of the masses."

Shri Mool Chand Daga.

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, जिन माननीय सदस्य ने यह संकल्प रखा था, वह सदन से चले गए हैं। उन्होंने अपना कर्त्तव्य नहीं निभाया है। हालांकि मैंने उनको इस प्रांगण में देखा था, मगर वह सदन से चले गए हैं।

सबाल है ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का माननीय सदस्य ने अपने संकल्प में तीन बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि हमने जो प्रोग्राम. बनाया था, उसके अन्तर्गत इच्छित काम हम नहीं कर सके। उसका कारण उन्होंने यह बत या है कि लालफीताशाही के कारण हम काम नहीं कर पाए । उन्होंने परामर्श दिया है कि हमें अपने नैतिक मूल्यों में सुधार करना चाहिए। नैतिक मूल्य क्या है, यह विरोधी दल वाले ज्यादा समझते हैं। नैतिक मूल्य यह है कि सदन की कार्यवाही चलनी चाहिए। लेकिन इन्होंने यह किया कि सदन की कार्यावही नहीं चलने दी, उसमें बाधा उपस्थित की, सदन का समय नष्ट किया और इस तरह सारा दिन खराब कर दिया। फिर भी यह लोग हमें नैतिक मूल्यों के बारे में भाषण देते हैं।

प्रस्तावक महोदय ने कहा है कि हमारे देश में योजनाबद्ध विकास नहीं हुआ। हमने जो योजनायें बनाई हैं, जो कार्यक्रम बनाए हैं-आज हमारी छठी पंच-वर्षीय योजना समाप्त होने जा रही है -, हमें बिना हिचक के कहना चाहिए कि उनके लक्ष्यों को हम प्राप्त नहीं कर पाए हैं। उसका एक कारण है लालफीताशाही। हमारी जो योजनायें बनती हैं, वे किस प्रकार क्रियान्वित होती है ? 1958 में राजस्थान कैनाल की योजना बनी। स्वर्गीय गोविन्द वल्लभ पन्त ने उसका उद्घाटन किया। उन्होंने कहा था कि 1960 में राजस्थान कैनाल पूरी कर दी जायेगी वह 60 करोड़ रुपये की योजना थी, लेकिन आज वह योजना 600 करोड़ रुपये की हो गई है और अभी तक पूरी नहीं हुई है।

जितनी योजनायें हमने बनाई थीं, वे समय पर पूरी न होने के कारण हमारे विकास की गति में कमी रही। इसका सब से बड़ा कारण यह है कि हमारे जो सरकारी कर्मचारी भाई हैं, उन्होंने हमें उतना सहयोग नहीं दिया, जितना कि उन्हें देना चाहिए था। ये सरकारी कर्मचारी बड़े मजबूत लोग होते हैं और अगर मंत्री महोदय उनसे भी ज्यादा मजबूत हों, तभी वे

(श्री मूल चन्द डागा)

काम करा सकते हैं, अन्यथा सरकारी कर्मचारियों का पूरा सहयोग हमें नहीं मिलता।

माननीय सदस्य ने अपने संकल्प में जो कहा है, वह हमें मानना चाहिए। आज भी सरकारी दफतरों में जिस ढंग से प्रशासन धीमी गति से चलता हैं, लोग ठीक काम नहीं करते हैं, दफतर समय पर नहीं आते हैं, फाइलों का निपटारा नहीं होता है,

उसके बावत उन्होंने हमारा ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने बताया है कि हमें इस के लिए शिक्षा में परिवर्तन करना होगा। एक बहुत पुरानी बात है कि हर शिक्षा मंत्री ने यह कहा है कि शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन आज तक हम लोगों ने उस में परिवर्तन किया नहीं और पढ़े लिखे बेरोजगारों की भीड़ खड़ी हो गई। हमारी शिक्षा एक अच्छे नागरिक को देश के सामने पेश नहीं करती। आज कालेज से निकले हुए विद्यार्थी किस प्रकार का कर्तव्य देश के प्रति और समाज के प्रति अदा करते हैं वह आप सब जानते हैं। इसलिए संकल्प रखने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा है कि शैक्षिक और नैतिक मूल्यों को ऊंचा उठाया जाए। नैतिकता की जो बात है मेरी समझ में वह बहुत आदर्श की बात है। हमारे माननीय सदस्य केयूर भूषण जी इस पर बड़ा अच्छा भाषण दे सकते हैं। (व्यवधान) उस में मनोरंजन भी कम नहीं होगा। यह काले पानी अर्थात अंडमान निकोबार से आए हुए माननीय सदस्य भी उस को समझते हैं। आप तो इस पर बड़ा अच्छा भाषण दे सकते हैं। हम लोग तो कभी कभी स्वार्थ के कारण या प्रलोभन के कारण थोड़ा बहुत इन मूल्यों से अलग हुए हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 15 अगस्त को लाल किले से भाषण देते हुए यह कहा हैं कि नैतिक मूल्यों में गिरावट आई है।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : वेरी गुड।

श्री मूल चन्द डागा : हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर साहब ने उस की वेरी गुड का खिताब दे दिया तो मान लेना चाहिए कि बात बिलकुल सही है।

इस के लिए उन्होंने प्रशासनिक सुधार की बात कही, नैतिक मूल्यों में गिरावट की बात कही और उन्होंने कहा कि हमारा देश आगे इसलिए नहीं बढ़ पाया कि योजनाबद्ध विकास के द्वारा कम आय वालों की दशा नहीं सुधरी। हिन्दुस्तान में हम लोगों ने एन०आर०ई०पी० और आई०आर०डी०पी० का प्रोग्राम बनाया और यह निर्णय किया कि जितने विकास खंड हैं उन के द्वारा 1 करोड़ 50 लाख आदमी गरीबी रेखा से ऊपर लाए जायेंगे और उस के लिए आज गाँव गांव के अन्दर हम उन लोगों को आर्थिक सहायता देते है जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। हर ब्लाक के अन्दर तीन हजार कुटुम्ब को गरीबी रेखा से ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमारे जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उन का मोड़ गरीबों की ओर होने लगा है। उस पर भी विरोधी लोग आवाज उठाते हैं। जब हम गरीबों के अन्दर धन का वितरण करते हैं तो हमारे खिलाफ आवाज उठाते हैं। आई.आर. डी.पी. और एन.आर.ई.पी. के सारे प्रोग्राम हम ने चलाए हैं और जो शिक्षित बेरोजगार हैं उन को 25 हजार रुपये की धनराशि देने का कार्यक्रम भी बनाया। 15 अगस्त 1983 के दिन घोषणा की थी कि जगह जगह जो दो करोड़ पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं उन लोगों को भी रोजगार दिया जाए। अब कहां तक हम उस

में सफल हुए हैं या नहीं हुये हैं, उस का कारण यह है कि सरकारी अधिकारी लोग अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर पाते। जो लोग उन के ऊपर बैठे है उन की पकड़ उन के ऊपर नहीं होती है घुड़सवार जो होता है उसकी पकड़ मजबूत होनी चाहिये। वह घोड़े की लगाम को मजबूती से पकड़ता हैं तो घोड़ा ठीक चलता है और जब लगाम हाथ में नहीं रहती है तो घोड़ा इधर उधर चलता है। हमारे संसत्सदस्यों को मालूम है कि काफेपोसा मौजूद है लेकिन स्मगलिंग भी हो रही है। नैपाल के बार्डर से, महाराष्ट्र और गुजरात के कोस्ट से अरबों रुपये का माल अभी भी तस्करी में आता हैं। हमारे आजाद साहब कहते हैं कि वे एसेंशियल कमाडिटीज ऐक्ट को सख्ती के साथ लागू करना चाहते हैं लेकिन वे कानून के द्वारा जितनी ज्यादा सजा का प्रावधान करते हैं, काला धंधा करने वाले लोग अपना धन उतना ही बढ़ाते जा रहे हैं। आज भी काला धंधा बढ़ रहा है और मुनाफाखोर लाभ उठा रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ लोग अपने स्वार्थहित में प्रान्तों में जातिवाद और धर्म के आधार पर झगड़े कर रहे हैं। इसलिये यह जो संकल्प रखा गया है, उसकी भावना तो ठीक है और अगर सारे देश के लोग मिलकर इसके अनुसार चलें तभी लाभ मिल सकता है। लेकिन एक दृष्टि रखने वाले लोग केवल एक काम करते हैं। जब भी सरकार कोई रचनात्मक काम करना चाहती है, उसमें वे बाधा डालते हैं।

आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि देश में परिवार कल्याण, परिवार नियोजन का काम ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़े। यदि जनसंख्या में वृद्धि न हो तो हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं। आज हम अपने आदमियों को अंतरिक्ष में भेज चुके हैं। विज्ञान और टेक्नोलाजी के क्षेत्र में भी हम बहुत आगे बढ़े हैं। आज हमारा देश नान-एलाइन्ड कन्ट्रीज का चेयरमैन है। विदेशों में हमारा गौरव बढ़ा है। अभी कुछ क्षेत्रों में हम पीछे हैं और उसके लिए हमें अपने संविधान में संशोधन करना होगा। आर्टिकल (311) में संशोधन होना चाहिये और सरकारी कर्मचारियों पर एकाउन्टेबिलिटी डालनी चाहिए। आज एक मन्त्री किसी आई० ए० एस० आफिसर के खिलाफ कार्यवाही करने की इच्छा रखते हुये भी वह उसको सस्पेंड नहीं कर सकता है क्योंकि वह कानून से बंधा हुआ है। आज 36 साल के बाद भी वह कानून अभी तक नहीं बन पाया है जिसके आधार पर मन्त्री किसी करप्ट आफिसर को नौकरी से निकाल सके इसलिए हमें कानून में परिवर्तन करना होगा। आज हमारी 84 परसेंट रेवेन्यु सरकारी कर्मचारियों पर खर्च हो जाती है। तीन घंटे में वे सिर्फ ढाई लाइन ही लिखते हैं। बहुत कम कर्मचारी ईमानदारी और मेहनत से काम करते हैं। हम चिट्ठी लिखते हैं तो उसका जवाब भी नहीं देते हैं। आज जनता के प्रतिनिधि 18 घंटे काम करते हैं लेकिन वे लोग 10 से 5 बजे के बीच में तीन बार चाय पीते हैं और 6 बार बातें करते हैं क्रिकेट को और पिक्चर्स की। इसलिये में समझता हूं हमें संविधान में परिवर्तन लाकर समाजवादी समाज के लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिये चाहे एक दिन हाउस ही क्यों न बढ़ाना पड़े। जिनके आधार पर हम लोग काम कर सकें। ये बक्त है समाजवादी समाज लाने का। जिन लोगों के पास धन जमा ही गया है वह आपके छोटे मोटे कानून से नहीं निकलेगा। इरादा मजबूत होगा तो सफ़लता जरूर मिलेगी इससे सबका मनोबल बढ़ेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और मुझे आशा है कि देश आगे बढ़ेगा।

MR. CHAIRMAN : Shri Zainal Abedin not present. Shri Sudhir Giri-not present, Prof. Ajit Kumar Mehta-not present, Shri

(Mr. Chairman)

Rajesh Kumar Singh-absent, Shri R.L.P. Verma-not present, Shri Ramavatar Shastri-not present, Shri S.T.K Jakkayan-not present. Since there is nobody here to speak, the Minister may intervene on this.

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : सभापति महोदया अभी श्री डागा जी ने सुझाव दिए हैं श्री राम लाल राही जी के प्रस्ताव के ऊपर जो इनकम ग्रुप के लोगों के प्लान, डेबलपमेंट, रुरल एरियाज में जो इनेडिक्वेसीज हैं, उनको दूर करने के लिये जो सुझाव दिए गए हैं, पालिसीज बनाकर—

by laying emphasis on educational and moral values and by revamping the administrative structure so as to ensure integrated development of the rural areas for upliftment of the masses.

यह बहुत एक अच्छा ख्याल था और उसके ऊपर श्री डागा जी सहित 8 माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। श्री राम लाल राही, इन्होंने इसको मूव किया, श्री चिन्तामणि पाणिग्रही, श्री चित्ताबसु श्री फैलीरो, श्री मनी राम बागड़ी, श्री राम प्यारे पनिका, श्री राम विलास पासवान, इन सब ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। डागा जी ने जो सूझाव दिए हैं, उसमें एक बात से में सहमत नहीं-हूं जो उन्होंने कह दिया कि सारे के सारे अफसर...।

श्री मूल चन्द डागा : सारे नहीं कहा, कुछ अफसर।

श्री बूटा सिंह : क्योंकि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेस जो हैं -

they are known for their efficiency, their patriotism, their commitment to the nation and, no doubt, a lot can be done. We have to improve the Services but definitely we cannot ignore those young and committed Indian officers who are serving the nation to the best of their ability. Those who are not doing their best, we will have to improve and tone up the administration so as to ensure that the people of the country are served in a better position.

राही जी का रेजोल्यूशन खासकर ग्रामीण क्षेत्र के बारे में है। जितने भी सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये हैं, पिछले हप्ते और अभी डागा जी ने सूझाव दिए हैं, वे सारे के सारे सूझाव हम गवर्नमेंट आफ इंडिया के जो मंत्रालय हैं या विभाग हैं, उनके पास भेजेंगे और कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इंप्लीमेंटेशन करवाया जा सके। चूंकि रामलाल राही जी यहां पर नहीं हैं, वह अगर यहां पर होते तो मैं उनसे कह देता उनके विचारों का आदर करते हुये कि इस प्रकार का प्राईवेट मेम्बर रेजोल्यूशन एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको वापिस ले लिया जाये। आज चूंकि वे नहीं हैं इसलिए गवर्नमेंट का जो दृष्टिकोण है, वह मैंने बता दिया है। जितने भी यहां पर माननीय सदस्यों ने विचार प्रकट किए हैं, वह सब नोट कर लिये हैं। वह चाहे रुरल डवलपमेंट, एग्रीकल्चर, इरीगेशन, एजुकेशन या मेरी स्पोर्टस मिनिस्टरी के हों, हम उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा कार्यवाही करके कोशिश करेंगे कि गाँव में रहने वाले लोगों को जितनी सुविधायें दी जा सकती हैं, वह दी जा सकें। डागा जी ने जो कहा है कि सोशलिस्टीक पालिसीज बनाकर लोगों की सेवा करें, उसके ऊपर हम प्रयत्नशील रहेंगे। चूंकि यह प्राईवेट मेम्बर रेजोल्यूशन है इसलिए इसको नहीं माना जा सकता। मैं सदन से आग्रह करूंगा कि यह प्रस्ताब इस शक्ल में नहीं जाना माना जा सकता। गवर्नमेंट इसके ऊपर विचार करेंगी। माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिए हैं, उन पर हम कार्यवाही करेंगे।

MR. CHAIRMAN Shri Ram Lal Rahi is not here. He was to reply to the debate. So, I will but the Resolution to the vote of the House. The question is :

> "That this House is of the opinion that Government have failed to ameliorate the lot of low income group people through planned development of rural areas on account of serious inadequacies in the administrative machinery and therefore recommends to the Government to devise pragmatic policies by laying emphasis on educational and moral values and by revamping the administrative structure so as to ensure integrated development of the rural areas for upliftment of the masses."

The Resolution was negatived.

MR. CHAIRMAN : Shri R.L.P. Verma is not present. Shri Sunil Maitra and Shri Ajit Kumar Saha are also not present. The Private Members' Business is over.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, SPORTS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BUTA SINGH) : Now, that the Private Members business is over, we have with us still two hours according to the normal sitting of the House But I will request the hon. Chair to permit us to sit longer so that we can go through the Agenda which has been fixed for today. Therefore, my submission to the House is that the House should give its approval to sit till today's agenda is disposed of.

MR. CHAIRMAN : Is it the sense of the House that the House should sit till today's business is over ?

SEVERAL HON. MEMBERS : Yes.

MR. CHAIRMAN : so I take up the next item.

15.58 hrs.

MOTION RE : TWENTY-SIXTH AND TWENTY-SEVENTH REPORTS OF COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES AND FIRST AND SECOND REPORTS OF COMMISSION FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES *Contd.*

MR. CHAIRMAN : Shri Ram Pyare Panika, Shri A.C. Das, Shri Sultanpuri and Shri Bhuria are not present. Therefore, Shri Giridhar Gomango will speak.

SHRI GIRIDHAR GOMANGO (Koraput) : Madam Chairman, the reports submitted to the House relate to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commission. We are discussing today both the Scheduled Castes and Scheduled Tribes together, but it would have been better if we had discussed them separately.

16.00 hrs.

It is because, Madam, one is a constitutional body and another is the Commission which was constituted under the Executive order. There are nearly 1593 recommendations and the Twenty-sixth Report and the Twenty-seventh Report as well as the First and Second Reports of the Commission put together and discussed one after another, I think it will take a longer time. Therefore, I would like to give some suggestions regarding the recommendations which are important to be considered and accepted by the Government for implementation immediately.

In the Twenty-Sixth Report of the Commissioner the important recommendations are No. 1, 4, 5, 12, 13, 14, 15 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 40, 44, 48, 49 50, 51, 52, 54, 59, 60, 110, 132, 226, 227, 233, 237, 242, 250, 257, 263, 264, 265, 267, 269, 271, 290 and 303. These are the most important recommendations which should be accepted. Almost all the recommendations which are given in the Reports nearly 1,595, should be accepted for implementation.